सुभाषित *इस लोकमें करने योग्य कर्मोंको करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्मोंका लोप नहीं होता।* ❑ **ईशोपनिषद्**

कुवैतसे रिश्तोंको नयी ऊंचाई

आतंकवाद पूरे विश्वके लिए बड़ी चुनौती और गम्भीर समस्या है। विश्वका ऐसा कोई देश नहीं है जो कमोबेश इस समस्यासे पीड़ित नहीं हो लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह है कि इस वैश्विक समस्यासे निबटनेके लिए सभी राष्ट्र एकमत नहीं हो सके हैं और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओंकी भूमिकामें कुछ औपचारिकताओंतक सिमट गयी है, जो समस्याको और गम्भीर बनानेमें सहायक बन रहा है। इस सन्दर्भमें भारत आतंकवादके खिलाफ संघर्षका अलख जगाये हुए है और कई देशोंने भारतके इस महत्वपूर्ण अभियानमें खुले मनसे साथ दिया। इसी क्रममें खाड़ीका एक और देश कुवैत भारतके साथ आ गया है, जिससे भारतको इस अभियानमें ऊर्जा मिली है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीकी दो दिवसीय कुवैत यात्राकी यह बड़ी उपलब्धि है। प्रधान मंत्री मोदीकी दो दिवसीय कुवैत यात्रा अत्यन्त ही सफल और सार्थक रही। कुवैत सरकारने प्रधान मंत्री मोदीको सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान 'द आर्डर आफ मुबारक अल-कबीर' से सम्मानित कर न केवल भारतका गौरव बढ़ाया है, बल्कि इससे इस्लामिक देशोंको भी बड़ा सन्देश गया है। पाकिस्तान और बंगलादेशको भी नसीहत मिली है, जहां आतंकवादका पोषण किया जाता है। लगभग ४३ वर्षोंके बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्रीकी कुवैत यात्राको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और विश्वकी नजरें इस यात्रापर टिकी हुई हैं। मोदीने अमीर शेख मेशाल और प्रधान मंत्री शेख अहमदसे अलग-अलग वार्ता की और दोनों देशोंके बीच सहयोगके विभिन्न मुद्दोंपर गहन मंत्रणा भी की। विशेष बात यह है कि कुवैत खाड़ी क्षेत्रमें भारतका एक और राजनीतिक साझीदार देश होगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश पहलेसे ही भारतके रणनीतिक साझेदार हैं। सीमापार आतंकवादके खिलाफ संघर्षमें हरसम्भव सहयोगका वादा करनेवाले कुवैतसे रक्षा क्षेत्रमें व्यापक सहयोग करनेको लेकर ऐतिहासिक समझौता भी काफी महत्वपूर्ण माना जायगा। कुवैत अगले महीने खाड़ी देशोंके संघटन जीसीसीका अध्यक्ष बनने जा रहा है। इससे खाड़ी देशोंके साथ भारतके सम्बन्धोंमें और मजबूती आयगी। आनेवाले दिनोंमें जहां दोनों देशोंके बीच सम्बन्धोंको नयी ऊंचाई मिलेगी, वहीं आपसी सहयोगको विस्तार भी मिलेगा। भारत-कुवैतके बीच प्रगाढ़ सम्बन्धोंसे पाकिस्तान सहित उन देशोंकी चिन्ताएं भी बढ़ जायगी, जो भारतको बुरी नजरसे देखते हैं।

अनुकरणीय प्रयास

बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जो देशमें पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जा चुका है। इसके बावजूद इस प्रथाका प्रचलन जारी रहना न सिर्फ चिन्ताका विषय है, बल्कि राज्योंकी कार्यप्रणालीपर भी सवाल खड़ा करता है। इस सामाजिक बुराईको खत्म करनेके लिए असमकी हिमन्त बिस्व सरमा सरकार पूरी तरह कटिबद्ध दिख रही है और बाल विवाहके खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। इस स्म्बन्धमें राज्य सरकारका 'बाल विवाहरोधी अभियान' अत्यन्त महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। इसके तहत बीते २१-२२ दिसम्बरकी रातसे शुरू किये गये तीसरे चरणके अभियानमें २४ घण्टेके भीतर ४१६ लोगोंको गिरफ्तार किया गया और ३३५ मामले दर्ज किये गये हैं। इसके पूर्व फरवरी, २०२३ में अभियानके पहले चरणमें ४,५१५ मामले दर्ज किये गये थे और ३,४८५ लोगोंको गिरफ्तार किया गया था, जबकि अक्तूबरमें चलाये गये दूसरे चरणमें ७१० मामले दर्ज किये गये और ९१५ लोगोंको गिरफ्तार किया गया था। चरणबद्ध ढंगसे चलाये जा रहे अभियानमें तीनों चरणोंमें अबतक कुल ५,५६० मामले दर्ज किये जा चुके हैं और ४,८१४ लोग गिरफ्तार किये गये हैं। यह आंकड़ा मुख्य मंत्री हिमन्त बिस्व सरमाके कथनका प्रमाण है कि हम इस सामाजिक बुराईको खत्म करनेके लिए कठोर कदम उठाते रहेंगे। देशमें आजादीके बादसे ही प्रचलित सतीप्रथा और बाल विवाह जैसी अन्य कुरीतियोंको खत्म करनेके लिए तत्कालीन मनीषियों और समाज सुधारकोंने लम्बी लड़ाई लड़ी और विरोधका खुलकर सामना भी किया। साथ ही समाजके बीच जाकर लोगोंको बुराइयोंके दुष्परिणामसे अवगत कराते हुए इसे रोकनेका अथक प्रयास किया। बादमें इन प्रथाओंको रोकनेके लिए दण्डात्मक कानून भी बना जिससे सतीप्रथा तो खत्म हो गयी लेकिन बाल विवाह अब भी जारी है, जो देश, समाज और परिवारके हितमें नहीं है। इस सन्दर्भमें असम सरकारका प्रयास उचित और सराहनीय है। यह अन्य राज्योंके लिए भी अनुकरणीय है।

लोक संवाद

असंयमी होते राजनीतिज्ञ

महोदय,-सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलोंके बीच राजनीतिक बयानबाजी और कटुता दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और प्रत्येक पक्ष राजनीतिक विरोधियोंपर कटाक्ष करने और उनका उपहास करनेका कोई मौका नहीं छोड़ता। कई बार इससे विडंबनापूर्ण और आत्म-विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। वे दिन चले गये जब संसद राजनीतिक विरोधियोंके बीच ज्ञानवर्धक भाषणों और मैत्रीपूर्ण वार्ताका स्थान हुआ करती थी, जिसमें कभी कोई कटुता नहीं दिखती थी। पीलू मोदी, जिनका सैंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब था, राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज एक-दूसरेपर कटाक्ष करते थे, लेकिन ऐसा करते समय उनके बीच कटुताका कोई निशान नहीं था। अपनी बात जोर-शोरसे और स्पष्ट रूपसे रखते थे और बिना किसी रुकावटके अपनी बात कहनेकी अनुमति देते थे। नेता संसदके बाहर अकसर मिलते थे और सामयिक मुद्दोंपर चर्चाके लिए भोजन करते थे। आजकल स्थिति काफी विपरीत है, जिसमें स्पष्ट रूपसे एक-दूसरेके प्रति कोई सम्मान नहीं है। कटुता आम बात हो गयी है। संसदकी काररवाईको रोकना सामान्य बात है। हालांकि यह कोई नयी बात नहीं है, क्योंकि यूपीए शासनके दौरान भाजपाके सदस्य भी ऐसा ही करते रहे हैं। जाहिर है कि संवादकी कमी है और नेता शायद ही कभी राजनीतिक विरोधियोंसे अनौपचारिक रूपसे मिलते हैं। विडंबना यह है कि उन्हें यह अहसास ही नहीं होता कि वे जिन मुद्दोंपर दूसरोंकी आलोचना करते हैं, उनमेंसे कुछ मुद्दोंपर वे खुद भी इससे भी बदतर अपराधी रहे हैं! कांग्रेस, जो निस्संदेह संविधानका उल्लंघन करनेके मामलेमें सबसे बड़ी अपराधी है, संविधानमें संशोधन करनेकी कोशिश करनेके लिए भाजपाकी आलोचना करती रही है। राहुल गांधी सहित इसके नेता संविधानकी एक प्रति लेकर देशभरमें घूम रहे थे और दावा कर रहे थे कि भाजपा इसे बदलनेके लिए तैयार है। प्रियंका गांधी और पार्टीके अन्य नेता भी भाजपापर संविधानको ख़त्म करनेकी कोशिश करनेका आरोप लगा रहे हैं। संयोगसे उन्होंने लोकसभासे अपना अभियान जारी रखा, जहां इससे पार्टीको राष्ट्रीय स्तरपर कुछ लाभ मिल सकता था, यहांतक कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावोंमें भी, जहां इस मुद्देपर शायद ही कोई चर्चा हुई। संविधानके रक्षकके रूपमें काम करने या करनेकी कोशिश करनेवाली कांग्रेस यह भूल रही है कि यह इंदिरा गांधी ही थीं, जिन्होंने आंतरिक आपातकाल लगाया था और लोगोंके मौलिक अधिकार भी छीन लिये थे। इतना ही नहीं, केन्द्रमें पार्टीकी सरकारें विपक्ष शासित राज्य सरकारोंको बिना सोचे-समझे बर्खास्त कर रही हैं। मौजूदा भाजपा सरकारपर मणिपुरमें बीरेन सिंहके नेतृत्व वाली अपनी ही पार्टीकी सरकारको बर्खास्त न करनेका आरोप लगाया जा सकता है, जो सरकारको बर्खास्त करनेके लिए एक उपयुक्त मामला है। दूसरी ओर भाजपा नेता जाति जनगणनाकी मांग करके कांग्रेसको विभाजनकारी पार्टी कह रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने हालमें पार्टीपर राजनीतिक लाभके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को विभाजित करनेका प्रयास करनेका आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओबीसी समुदायके प्रभावको कम करनेके लिए इसे छोटे जाति समूहोंमें विभाजित करके इसकी एकीकृत पहचानको ख़त्म करनेकी कोशिश कर रही है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियोंपर एक जातिको दूसरी जातिके खिलाफ खड़ा करनेका आरोप लगाया था और लोगोंसे एकजुट रहनेकी अपील करते हुए कहा था, एक है तो सुरक्षित है। केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने भी इस सप्ताह संसदमें कहा कि कांग्रेस विभाजनकारी है क्योंकि वह धर्म आधारित कोटा लानेके लिए ५० प्रतिशतकी सीमाको तोड़ना चाहती थी। कांग्रेसपर विभाजनकारी होनेका आरोप लगाना और उसपर समाजमें दरार पैदा करनेका आरोप लगाना वास्तवमें बहुत ही विडंबनापूर्ण है। यह आरोप भाजपाके लिए और भी सही है, जिसने हिंदू-मुस्लिम कथाको अपने अभियानका हिस्सा बना लिया है और समाजमें दो समुदायोंके बीच जहर घोल दिया है, जिससे आपसी संदेह पैदा हो रहा है। दूसरी ओर पार्टी कांग्रेसपर बहुसंख्यक समुदायकी कीमतपर अल्पसंख्यकोंको खुश करनेका आरोप लगाती है। ये बर्तनको काला कहनेके क्लासिक उदाहरण हैं। अब समय आ गया है कि राजनीतिक नेता बेबुनियाद आरोप लगाकर अपना हित साधनेसे बचें और अकसर मिलकर अनौपचारिक रूपसे मुद्दोंपर चर्चा करके आपसी संवादको बेहतर बनायें। **-बी. पब्बी, वाया ईमेल।**

चीनसे सतर्कता जरूरी

चीनके साथ शांतिपूर्ण संबंधोंकी दृष्टिसे बीजिंगमें भारतीय सुरक्षा सलाहकार और चीनी विदेश मंत्रीकी भेंट महत्वपूर्ण घटना है। रूसके कजानमें प्रधान मंत्री मोदी और चीनके राष्ट्रपति शी जिनपिंगकी द्विपक्षीय वार्तामें सीमा-विवादको लेकर जो सहमति बनी थी, उसी दिशामें सकारात्मक वातावरण बना है।

❑ **विकेश कुमार बडोला**

भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यीने परस्पर संबंधोंको सामान्य करनेके लिए विभिन्न कार्यबिंदुओंपर विमर्श किया है। इनमें प्रमुख है लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखाके विवादको समाप्त करना। इसके लिए दोनों देशोंकी सेनाएं धरातलपर सक्रिय होने लगी हैं। विवादित सीमा-रेखाके समीप दोनों ओर अस्थायी रूपमें स्थापित सैन्य चौकियां हटानेका काम आरम्भ हो गया है। अस्त्र-शस्त्रकी तैनातियां रोक दी गयी हैं। हजारोंकी संख्यामें सैनिक सीमा क्षेत्रसे वापस चले गये हैं। इस वातावरणमें विशेष प्रतिनिधियोंके बीच यह सहमति भी बनी है कि अब सीमा क्षेत्रोंके माध्यमसे होनेवाली व्यापारिक गतिविधियोंको पुन: सामान्य कर दिया जाय। सीमाके दोनों ओर स्थित और दोनों दिशाओंसे होकर इधर-उधर बहनेवाली नदियोंके स्वामित्व एवं व्यावसायिक उपयोगके संबंधमें आवश्यक सूचनाओं एवं जानकारियोंका आदान-प्रदान करना भी सहमतिके बिंदुओंमेंसे एक है। इसके अतिरिक्त एक-दूसरेकी सांस्कृतिक-धार्मिक मान्यताओंके सम्मानको बनाये रखनेकी दृष्टिसे मानसरोवरकी यात्रा एवं पर्यटनको भी पूर्वकी भांति सामान्य बनानेकी संभावनाएं व्यक्त की गयी हैं। विशेष प्रतिनिधियोंके बीच सहमतिके कुल छह बिन्दु हैं, जिनपर दोनों पक्षोंका शत-प्रतिशत एकमत होना अभी संभव नहीं लगता, क्योंकि जबतक चीन वास्तविक रूपमें भारतकी भौगोलिक संप्रभुताका सम्मान करते हुए सीमा क्षेत्रमें सैन्य हस्तक्षेप पूर्ण रूपमें बंद नहीं करता, तबतक संबंधोंके समानांतर आशंकाएं भी बनी ही रहेंगी।

क्षेत्रीय संप्रभुताके आधारपर भारत अपनी प्रवृत्तिको नहीं बदल सकता। वास्तवमें चीनको भारतसे केवल व्यापारिक-आर्थिक आकांक्षाएं हैं। दस वर्ष पूर्वके आधेसे अधिक असंघटित भारतीय व्यापारिक क्षेत्रपर चीनके ही सस्ते सामानका आधिपत्य था। चीनके साथ भारतका कोई भी संबंध या आर्थिक व्यवहार अत्यधिक सावधानीके साथ निर्धारित होना चाहिए। चीनकी आसन्न आधुनिक प्रगति, उसकी बौद्धिक प्रखरताको समझकर कोई भी देश उसे केवल शत्रु भावसे नहीं देखना चाहेगा। इस आधारपर विचार करें तो भारतीयोंको चीनके प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा।

वैसे देखा जाय तो इस समय द्विस्तरीय युद्धोंके कारण अनेक वैचारिक, राजनीतिक, सामरिक, भूकूटनीतिक एवं आर्थिक ध्रुवोंमें विभाजित दुनियामें पूरे चार वर्षके बाद भारत एवं चीनका पारस्परिक संबंध सुधारनेका प्रयास तथा इस संबंधमें पहले कजानमें मोदी-शीकी भेंटके बाद बनी परस्पर सहमति और अब इसी सहमति की निरंतरतामें बीजिंगमें डोभाल-वांग यीके बीच हुई वार्ता वास्तवमें एक सकारात्मक एवं आशाजनक घटना है। यह न केवल चीन और भारतके लिए अपितु दुनियाके लिए भी एक उपयोगी घटना है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासनके द्वितीय पंचवर्षीय कार्यकालमें पहले कोरोना महामारीके कारण देशी-विदेशी व्यवस्थाएं चरमराई थीं और फिर कोरोना कालमें ही गलवान घाटीकी सीमापर भारत एवं चीनके सैनिकोंके मध्य रक्तरंजित हिंसक भिड़न्त हो गयी थी। इस कारण दोनों देशोंके कई सैनिकोंकी मृत्यु हो गयी थी। चार वर्ष पूर्व २०२० में हुई यह घटना अप्रत्याशित थी। इससे पहले दोनों देशोंके सैनिकोंकी ऐसी भिड़न्त कभी नहीं हुई थी। इस घटनाके बाद चीनके प्रति भारतकी दृष्टि अनुदार हो गयी। भारतीय शासन सहित जनताने माना कि चीनी सैनिकोंका ऐसा दुस्साहस शी जिनपिंगके रूपमें चीनी राष्ट्रपतिकी अनुमतिके बिना हो ही नहीं सकता था। पूर्वमें लद्दाख भूक्षेत्रमें दोनों देशोंकी सीमाका विवाद वर्षोंसे लंबित है। इसके समाधान हेतु भारत-चीनके मध्य अनेक वार्ताओंके माध्यमसे विविध प्रयास हो चुके हैं, किन्तु इस संबंधमें चार वर्षतक पहलेतक कुछ भी सकारात्मक सहकारिता आधारित कार्य दोनों ही पक्षोंकी ओरसे नहीं हो सके थे। गलवानकी सैनिक-मुठभेड़के बाद तो दोनों देशोंके राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध ही नहीं अपितु व्यापारिक-आर्थिक संबंध भी इस सीमातक अस्वस्थ हो चुके थे कि मोदी और शी जिनपिंगके बाद तबसे कोई भी द्विपक्षीय वार्ता ही नहीं हुई थी।

हालांकि विशेष प्रतिनिधियोंकी वार्ता कितनी सफल रही है, इसका प्रभाव तब दिखेगा जब सीमाक्षेत्र पूर्वकी भांति केवल सैद्धांतिक स्तरपर ही विवादास्पद रहेगा और सीमाओंपर दोतरफा सैन्य घेराबंदी एवं हथियारोंकी तैनाती पूरी तरह बंद होगी। चीन एक आसान देश नहीं है। यदि वह हैसियतके हिसाबसे अमेरिका जैसे षड्यंत्रकारी देशके बराबर पहुंच सका है तो यह टेड़ी कूटनीतिके बिना संभव नहीं था। उसकी ऐसी प्रवृत्ति वर्षोंसे रही है। भारतकी क्षेत्रीय संप्रभुता, भारतीयताके मान और भारतीय विकासकी संभावनाओंके लिए वह खुदके विकसित होनेके प्रमुख आधार अपनी टेड़ी प्रवृत्तिको कभी नहीं बदल सकता। वास्तवमें चीनको भारतसे केवल व्यापारिक-आर्थिक आकांक्षाएं हैं। वह भी इसलिए हैं क्योंकि भावनात्मक स्तरपर भारतीय लोग चीनकी अतिक्रामक वृत्तिके कारण कितने ही उसके विरोधी हो जायं, परन्तु कई दशकोंसे अधिसंख्य आधुनिक वस्तुओं एवं सेवाओंके लिए तो वे उसपर ही निर्भर रहते आये हैं।

दस वर्ष पूर्वके आधेसे अधिक असंघटित भारतीय व्यापारिक क्षेत्रपर चीनके ही सस्ते सामानका आधिपत्य था। जिस प्रकार चीन अपने व्यापारिक प्रसारके लिए भ्रष्टाचारको विकासशील देशोंमें एक अस्त्रकी भांति उपयोगमें लाता रहा है, भारत जैसे देशमें चीन द्वारा इस आधारपर आर्थिक आधिपत्य करनेकी इच्छाशक्तिको तबतक ध्वस्त नहीं किया जा सकता है जबतक यहां एक-एक नागरिक, शासकीय-प्रशासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी तथा प्रधान मंत्री सहित हरेक नेता सत्यनिष्ठाके साथ राष्ट्रसेवक नहीं बन जाता, जो अभीके संसदीय परिदृश्यको देखकर दूर-दूरतक असंभव ही प्रतीत होता है। चीनके साथ भारतका कोई भी संबंध, कार्य व्यवहार या आर्थिक व्यवहार अत्यधिक सावधानी एवं जागरूकताके साथ निर्धारित होना चाहिए। चीनकी आसन्न आधुनिक प्रगति देखकर और हर आधुनिक समस्याको राष्ट्रीय कल्याणकी संभावनामें रूपांतरित करनेकी उसकी बौद्धिक प्रखरताको समझकर, भारत ही नहीं कोई भी देश उसे केवल शत्रु भावसे नहीं देखना चाहेगा। इस आधारपर विचार करें तो भारतीयोंको झूठी देशभक्ति त्याग कर चीनके प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर हमें चीन शत्रुके अतिरिक्त एक ऐसा शिक्षक भी प्रतीत होगा, जो हमें प्रेरित करेगा कि हम अपने देशकी संसदीय विसंगतियोंकी आपदाको एक नवीन राष्ट्रभक्तिके अवसरमें रूपांतरित करें।

मलेरियापर भारतकी जीत

डब्ल्यूएचओने भारतमें मलेरियासे होनेवाली मौतोंमें कमीको उल्लेखनीय बताया है, जिसका निश्चय ही नोटिस लिया जाना चाहिए। भारतमें मलेरियाके मामलोंमें आयी कमीसे एचबीएचआईवाले स्थानिक देशोंके समूहसे बाहर निकल गया है।

❑ **डा. ओ.पी. त्रिपाठी**

विश्व स्वास्थ्य संघटन द्वारा जारी जारी विश्व मलेरिया रिपोर्टमें भारत आधिकारिक तौरपर 'उच्च बोझ-उच्च प्रभाव' (एचबीएचआई) वाले स्थानिक देशोंके समूहसे बाहर निकल गया है। दरअसल २०१९ में देशके चार राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगालमें मलेरिया उन्मूलनकी गति तेज करनेके लिए अभियान चलाया गया था, जिसका निश्चित तौरपर लाभ मिला है। रिपोर्टमें यह भी कहा गया है कि जिन कुछ देशोंमें मलेरियापर बेहतर ढंगसे काबू पाया गया है, उनमें भारत एक है। यह सुखद है कि पूरी दुनियामें पिछले दो दशकोंमें मलेरियाके खिलाफ जंगमें आशातीत सफलता मिली है। जिससे जहां मलेरियाके मामलोंमें तेजीसे गिरावट दर्ज की गयी है, वहीं मौतके आंकड़ोंमें कमी आयी है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छरोंके जरिये लोगोंके बीच फैलती है। संक्रमित एनोफेलीज मच्छरके काटनेसे प्लाज्मोडियम परजीवी फैलता है जो पीड़ितके रक्तमें प्रवेश करता है और व्यक्तिके लिवरमें चला जाता है, जहां यह प्रजनन करता है। परजीवी फिर रक्त प्रवाहके माध्यमसे यात्रा करते हैं और लाल रक्त कोशिकाओंमें प्रवेश करते हैं, जहां वे तेजीसे प्रजनन करते हैं और लाल रक्त कोशिकाओंको फाड़ देते हैं, यह चक्रोंमें दोहराया जाता है, जिससे तेज बुखारके साथ-साथ कंपकंपी और दर्दका चक्र शुरू हो जाता है। सबसे खराब मामलोंमें, मलेरिया कोमा और मृत्युका कारण बनता है। १९५३ में भारत सरकारने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (एनएमसीपी) शुरू किया जो घरोंका भीतर डीडीटीका छिड़काव करनेपर केन्द्रित था। पांच सालोंमें ही कार्यक्रमकी वजहसे मलेरियाकी घटनाओंमें आश्चर्यजनक कमी देखनेमें आयी। इससे उत्साहित होकर एक अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) १९५८ में शुरू किया गिया। इससे मलेरियामें और भी कमी आयी और उसका मृत्युकी वजह बनना थम गया। लेकिन १९६७ के बाद अति-आत्मसंतोष तथा मच्छरों द्वारा कीटनाशकोंके तथा मलेरिया-रोधी दवाओंके प्रति प्रतिकार क्षमता उत्पन्न कर लेनेके कारणोंकी वजहसे देश भीमें मलेरियाने फिर सिर उठा लिया।

१९९७ में भारत सरकारने अपना लक्ष्य रोगके उन्मूलनसे हटाकर उसके नियंत्रणपर केन्द्रित किया और कीटनाशकोंके सार्वत्रिक छिड़कावको रोक कर चुनिंदा भीतरी जगहोंपर छिड़काव शुरू किया। २००३ में राष्ट्रीय ज्ञात-कारण बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत मलेरिया नियंत्रणको अन्य ज्ञात-कारण बीमारियोंके साथ मिला लिया गया, क्योंकि ऐसी सभी बीमारियोंकी रोकथामके लिए एक ही रणनीति होती है जैसे रासायनिक नियंत्रण, वातावरण प्रबंधन, जैविक नियंत्रण, और निजी सुरक्षा उपाय आदि। २००५ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया, जिसके उद्देश्योंमें शामिल है मलेरिया सहित ज्ञात-कारण बीमारियोंपर नियंत्रण शामिल था। जागरूकता अभियानसे भी इस दिशामें लक्ष्योंको हासिल करनेमें मदद मिली है। दरअसल, मलेरियासे ज्यादा प्रभावित राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़में मलेरिया उन्मूलन अभियान युद्ध स्तरपर चलाया गया। इसके चलते भारतको डब्ल्यूएचओने उन देशोंमें शुमार किया है, जिन्होंने इस दिशामें आशातीत सफलता हासिल की है। सुखद यह है कि मलेरियासे अधिक प्रभावित देशों मसलन अफ्रीकी देशोंमें नयी वैक्सीनके ट्रायलके बेहतर परिणाम सामने आये हैं। ऐसेमें उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि हर साल जो लाखों लोग मलेरियाकी चपेटमें आते हैं, नयी वैक्सीनके प्रभावसे उनकी जानके जोखिमको कम किये जानेमें मदद मिल सकेगी। दरअसल, वैक्सीनके फेज-२बीके क्लीनिकल ट्रायलके परिणाम बताते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनेमें कारगर है। वैक्सीनकी प्रभावशीलता पचपन फीसदी बतायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मशहूर चिकित्सा पत्रिका लांसेटमें प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि वैक्सीन रक्तमें मौजूद मलेरियाकी वजह बननेवाले परजीवियोंके खिलाफ प्रभावी पायी गयी है। जिसे जीवनकी रक्षाके लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

डब्ल्यूएचओकी रिपोर्टके मुताबिक, २०१७ में भारत में मलेरियाके ६४ लाख मामले थे, जो २०२३ में घटकर बीस लाख रह गये। इस दौरान मलेरियासे होनेवाली अनुमानित मौतें भी ११,११० से घटकर ३,५०० रह गयीं। रिपोर्ट बताती है कि चिकित्सीय सुविधा और सजगता बढ़ानेसे भारतमें जहां मलेरियाके अनुमानित १.७७ करोड़ मामलोंको टाला गया, वहीं मलेरियाका जोखिम प्रति एक हजारकी आबादीपर बीससे घटकर १.५ पर आ गया, यानी इसमें ९३ प्रतिशतकी कमी आयी। वास्तवमें जागरूकता अभियानसे उत्पन्न चेतना तथा चिकित्सा सुविधाओंके विस्तारसे मलेरिया उन्मूलनमें खासी मदद मिली है। एक अनुमानके अनुसार कोई पौने दो करोड़ मलेरियाके मामलोंको टाला गया है। वहीं मलेरिया जोखिममें भी आशातीत गिरावट आयी है। विश्व स्वास्थ्य संघटनके अनुसार दक्षिण-पूर्व एशियाके आठ देश मलेरियासे सर्वाधिक प्रभावित थे, जिसमें भारतमें भी स्थिति विगतमें चुनौतीपूर्ण थी। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संघटन इस बातको लेकर चिन्तित था कि इस क्षेत्रमें सघन आबादीके चलते दुनियाकी एक-चौथाई आबादी निवास करती है। डब्ल्यूएचओने दक्षिण एशियाके इन देशोंमें मच्छरोंसे पैदा होनेवाले मलेरियापर अंकुश लगानेके लिए सहज उपचारकी उपलब्धता सुनिश्चित करनेको कहा था जिससे लोगोंके जीवनपर जोखिमको कम किया जा सके। यह तभी संभव था जब मलेरियाके प्रति संवेदनशील लोगोंतक सहजतासे उपचार पहुंचा सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भारत, इंडोनेशिया, बंगलादेश एवं नेपालमें मलेरियाके मामलोंमें गिरावट आयी है, वहीं म्यांमार, थाईलैंड एवं दक्षिण कोरियामें मलेरियाके मामलोंमें वृद्धिका ट्रेंड देखा गया है।

विश्व स्वास्थ्य संघटनने दक्षिण पूर्व एशियामें मलेरियाके खिलाफ लड़ाईमें मिली जीतकी प्रशंसा तो की ही है, उसने इस रोग वाहक मच्छरजनित बीमारीकी रोकथाम, निदान और उपचारतक समान पहुंच सुनिश्चित करनेके लिए जोखिम संभावित लोगोंपर ध्यान केंद्रित करनेके लिए कहा है। इसकी वजह यह है कि भारत, बंगलादेश, इंडोनेशिया और नेपालमें मलेरियाके मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और म्यांमारमें मलेरियाके मामलोंमें वृद्धि देखी गयी है। जाहिर है, मलेरियाके खिलाफ लड़ाई अभी जारी है। यही वजह है कि मलेरिया उन्मूलनपर २०२४ की रिपोर्ट जारी करते हुए डब्ल्यूएचओने दक्षिण-पूर्व एशियाकी कमजोर आबादीपर ध्यान केंद्रित करनेको इन देशोंकी सरकारोंसे विशेष तौरपर कहा है। डब्ल्यूएचओने इसके लिए मलेरियाकी पहचान, बचाव तथा इलाजकी प्राथमिकता सुनिश्चित करनेका आग्रह सरकारोंसे किया है। जिससे मलेरियाके मामलोंमें गिरावटसे लाखों जिन्दगियोंकी रक्षा की जा सके। ऐसेमें नयी वैक्सीनके उत्साहजनक परिणामोंसे मलेरियाके संदर्भमें संवेदनशील देशोंमें इसके खिलाफ लड़ाईको तेज करनेमें मदद मिलेगी। जो मानवताके लिए एक सुखद संकेत भी है।

नागवासुकी मंदिर

❑ **निमेष शास्त्री**

प्रयागराजमें इन दिनों महाकुंभकी तैयारियां जोरोंपर हैं। संगम नगरी प्रयागराजमें लगनेवाले इस मेलेमें देश-विदेशसे लोग स्नान करनेके लिए पहुंचते हैं। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सवके दौरान प्रयागराजके प्रमुख घाटोंके अलावा यहां स्थित कुछ मंदिरोंके दर्शन करना एक यादगार अनुभव हो सकता है। इन्हींमेंसे एक है नागवासुकी मंदिर। इस मंदिरका इतिहास बहुत ही पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिरके दर्शन किये बिना संगमसे लौटना अधूरी यात्राके बराबर है। इसलिए यदि आप महाकुंभ जायं तो नागवासुकी मंदिरके दर्शन कर खुदको कृतार्थ करें। आइये जानते हैं नागवासुकी मंदिरके बारेमें। जब औरंगजेबका भाला भी नहीं आया काम-धर्म और आस्थाकी नगरी प्रयागराजके संगम तटसे उत्तर दिशाकी ओर दारागंजके उत्तरी कोनेपर अति प्राचीन नागवासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिरमें नागोंके राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आनेवाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्रीकी यात्रा तबतक अधूरी मानी जाती है, जबतक वह नागवासुकीका दर्शन न कर लें। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारतमें मंदिरोंको तोड़ रहा था तो वह नागवासुकी मंदिरको खुद तोड़ने पहुंचा था। जैसे ही उसने मूर्तिपर भाला चलाया तो अचानक दूधकी धार निकली और चेहरेके ऊपर पड़नेसे वह बेहोश हो गया था। अंतमें उसे हताश और निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तबसे लेकर आजतक इस प्राचीन मंदिरकी महिमाका गुणगान चारों दिशाओंमें हो रहा है। यहां नागोंके राजा वासुकीने किया था विश्राम- पौराणिक कथाओंके अनुसार समुद्रमंथनमें देवताओं और असुरोंने नागवासुकीको सुमेरु पर्वतमें लपेटकर उनका प्रयोग रस्सीके तौरपर किया था, वहीं समुद्रमंथनके बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गये थे और भगवान विष्णुके कहनेपर उन्होंने प्रयागराजमें इसी जगह आराम किया था। इसी वजहसे इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णुसे नागवासुकीको प्राप्त हैं तीन वरदान-जानकार बताते हैं कि जब देवताओं एवं राक्षसोंको समुद्रमंथनके लिए बड़ी रस्सीकी जरूरत थी। तब नागोंके राजा नागवासुकी रस्सी बने थे। इनको भगवान विष्णुसे तीन वरदान प्राप्त हैं, जिनमेंसे पहला वरदान है कि संगममें स्नान करनेके बाद बिना इनके दर्शनके स्नान पूरा नहीं होगा। वहीं, दूसरा वरदान है कि इनके दर्शन मात्रसे ही कालसर्प दोष खत्म होता है। तीसरे वरदानमें खुद नगर देवता बेदी माधव प्रत्येक वर्ष इनकी पूजा करने आते हैं। यही वजह है कि कुम्भ और सावनमें इस मंदिरमें श्रद्धालुओंकी भारी भीड़ उमड़ती है।

समाजमें सन्तुलन बनाना आवश्यक

❑ **डा. वरिंदर भाटिया**

बेंगलुरूमें इंजीनियर अतुल सुभाष (३४) ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अपनी पत्नीकी ओरसे लगाये गये आरोपोंसे परेशान हो चुका था। उसका आरोप था कि एकके बाद एक धाराएं उसपर और उसके परिवारवालोंपर लगायी गयीं। हमारे समाजमें सिर्फ अतुलका ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामले आये हैं जिनमें पुरुषोंने महिलाओंके आरोपोंसे प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। विशेषज्ञोंके मुताबिक पुरुष उत्पीड़नके मामले तेजीसे बढ़ रहे हैं। अकसर समाजमें पुरुषोंकी शिकायतोंको गम्भीरतासे नहीं लिया जाता। मनोविज्ञानी कहते हैं कि महिलाओंकी प्रमुख शिकायतें अकसर पुरुषोंके नशेमें हिंसक होने, विवाहेत्तर संबंध रखने या परिवारकी उपेक्षा करनेसे जुड़ी होती हैं। इनपर काररवाई होती है, ले